pattern is faulty hundreds of yoga teachers were rendered surplus in the last session. The All India Kendriya Teachers Associations had to resort to agitation before it could be held in abeyance for the session and the Damoclean sword is still hanging over their heads. All categories of teachers were transferred last session but the physical education and yoga teachers were not because of this. I would like to ask the hon. Minister what he has in his mind to resolve this long over-due problem.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: About the yoga teachers, it is absolutely a separate category. The question is absolutely of a general nature whether lower level staff is being decreased or higher level posts are being increased. That is the main thrust of the question. If the hon. Member wants all the details, I will supply to him when he comes to me and nothing will be kept secret. Everything will be told.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन और जो नए नवोदय विद्यालय देश में खुले हैं, इनके बीच में आपस का रिश्ता क्या है और दोनों को क्या एक अथारिटी कंट्रोल करती है या अलग-अलग अथारिटी कंट्रोल करती है ?

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान इसी सदन में 8 तारीख को मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न की ओर दिलाते हुए जानना चाहूंगा कि उन्होंने नवोदय विद्यालय के प्रश्न के क्रम में कहा कि

"The Government has decided as of now to review the Navodaya Vidyalaya scheme."

तो क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों को एक क्रम में रखकर एक ही तरह से इसके वेतनमान और पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी और प्रशासन एक ढांचे से चलेगा या दोनों में समानता न होकर कोई विषमता होगी ? अगर विषमता होगी, तो वह कौन-कौन सी होगी ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, there are two questions about Navodaya Vidyalayas future prospects. The matter has been handed over to the review committee which has been set up recently, what is to be done about its future, how it will be replaced or whatever they want to do. So I would not be in a position to reply. The first question relates to the already existing position whether Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya are managed by one organisation. Now they are two separate entities handling both educational streams. Therefore, there is no one unit in control of these two organisations.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 186.

SOME HON. MEMBERS: What about Q N.. 185.

MR. CHAIRMAN: It has been transferred to the Ministry of External Affairs.

*185. [*Transferred to the 23rd May, 1990*]

पश्चिमी जर्मनी की संस्था एच.डी. डब्ल्यू. द्वारा पनडुब्बी के पूरे खाकों (ब्लू प्रिन्टस) का दक्षिणी अफ्रीका को बेचा जाना

*186. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी से एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बियों की खरीद करते समय इस आशय का समझौता हुआ था कि इन पनडुब्बियों

*सभा में यह प्रश्न सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा पूछा गया ।

के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज या जानकारी किसी अन्य देश को नहीं दी जाएगी,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि एच.डी.डब्ल्यू. और इसकी सहायक संस्था आई.के.एल. ने 29 अप्रैल, 1985 को इन पनडुब्बियों के ब्लू प्रिन्ट दक्षिणी अफ्रीका को बेचने के लिए उस देश के साथ एक समझौता कर लिया था, और

(घ) यदि हां, तो समझौते का उल्लंघन करने के लिए सरकार द्वारा सम्बद्ध कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं और अब इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही योजना क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना): (क) और (ख) संविदाओं की वर्गीकृत सूचना के संरक्षण संबंधी संगत प्रावधान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (**देखिये नीचे**)

(ग) समाचार-पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट छपी है कि मैसर्स एच.डी. डब्ल्यू. आई.के.एल. ने पनडुब्बी के डिजाइन संबंधी दस्तावेज/ब्लूप्रिण्टों की सप्लाई के लिए अप्रैल, 1985 में दक्षिण अफ्रीका के एक पोत कारखाने के साथ करार किया था।

(घ) भारत सरकार ने इस बारे में 1987-88 में मैसर्स एच०डी०डब्ल्यू० और जर्मन संघीय गणराज्य दोनों से लगातार पूछताछ की। उन्होंने सूचित किया था कि मैसर्स एच.डी.डब्ल्यू. के साथ की गई संविदा के "गोपनीयता खण्ड" या जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ किए गए "सुरक्षा करार" का उल्लंघन करते हुए मैसर्स एच.डी.डब्ल्यू. ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के बारे में कोई वर्गीकृत सूचना दक्षिण अफ्रीका को नहीं दी है। लेकिन मैसर्स एच.डी.डब्ल्यू. ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि टाइप 1500 पनडुब्बियों के मूल डिजाइन संबंधी दस्तावेज उनकी औद्योगिक सम्पत्ति थे और डिजाइन संबंधी ये दस्तावेज अन्य ग्राहकों को दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे।

इस विषय पर हाल की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर यह मामला राजनयिक माध्यम से जर्मन संघीय गणराज्य के साथ उठाया गया है ताकि इस बात की पूरी तरह एवं बारीकी से जांच हो सके कि क्या ऊपर उल्लिखित "गोपनीयता खण्ड" या ऊपर उल्लिखित "सुरक्षा करार" का कोई उल्लंघन हुआ है।

विवरण

मैसर्स एच.डी.डब्ल्यू. के साथ की गई संविदा का खंड 23.8

इस संविदा की विषय-वस्तु और इस संविदा के निष्पादन के दौरान प्राप्त की गयी समस्त सूचना/आंकड़े दोनों पक्षों द्वारा गोपनीय मांने जायेंगे और किसी अन्य सरकार और/या किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किये जायेंगे। केवल विक्रेता के उप-संविदाकारों/सप्लायरों को उतनी सूचना एवं आंकड़े दिये जायेंगे, जितने इस संविदा के निष्पादन के लिये जहां आवश्यक होंगे। परन्तु इसमे खरीददार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा कि वह "नौका" के कार्यकाल के दौरान अथवा इसके अनुरक्षण के लिये इन उपस्करों/प्रणालियों की मरम्मत आदि के लिये उपस्करों प्रणालियों के अन्य निर्माताओं के साथ बातचीत न कर सके।

तकनीकी सहायता के बारे में जर्मन संघीय गणराज्य के संघीय रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच करार

अनुच्छेद 4: वर्गीकृत सैन्य सूचना को प्रकट करना

(1) संविदा करने वाले पक्ष वर्गीकृत सैन्य सूचना प्रकट करने के बारे में एक सुरक्षा करार करेंगे (इस समझौते का प्रथम अनुपूरक) ताकि इस प्रकार के अनुपालन में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली वर्गीकृत सैन्य सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संविदा करने वाला कोई भी पक्ष, किसी भी रूप में, दूसरे पक्ष की बिना जानकारी तथा पूर्व सहमति के कोई भी वर्गीकृत सैन्य सूचना किसी तीसरे पक्ष या अनधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। परन्तु इन संविदाओं के कार्यान्वयन के लिये जहां तक आवश्यक हो, संविदा से जुड़े पक्षों और माँझगांव डॉक लिमिटेड को तीसरा पक्ष नहीं माना जायेगा।

(2) संविदा करने वाले पक्ष एक दूसरे को उक्त पनडुब्बियों में संशोधन, परिचालन, रख-रखाव और सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सभी सूचनायें देंगे, बशर्ते ये सूचनायें सम्बद्ध संविदाओं में शामिल न की गई हों।

वर्गीकृत सैन्य सूचना को प्रकट करने और उसका संरक्षण करने के बारे में तकनीकी सहायता संबंधी करार के लिये प्रथम अनुपूरक करार।

अनुच्छेद 7 : सुरक्षा का उल्लंघन

वर्गीकृत सूचना "वस-वरट्राउलीच" (गोपनीय) अथवा अधिक गुप्त सूचना के चोरी होने या अनधिकृत रूप से प्रकट होने के सन्देह की स्थिति में उत्पादक (औरीजीनेटिंग) देश की सुरक्षा एजेंसी (रक्षा मंत्रालय) प्राप्त करने वाली एजेंसी को राजनयिक माध्यमों से तुरन्त सूचना देगी।

गोपनीयता भंग होने के मामलों की जांच की जाएगी और उस देश की सक्षम एजेंसियों तथा न्यायालयों द्वारा अभियोग चलाया जाएगा, जिसके कानून, नियम एवं विनियम उन मामलों पर लागू होंगे। यह 10 जुलाई, 1981 के तकनीकी सहायता के बारे में हुए करार के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अध्यधीन है।

उत्पादक देश की सुरक्षा एजेंसी को इस संबंध में की गयी कार्यवाहियों के परिणामों की जानकारी दी जायेगी।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, first supplementary is: What is the latest situation? It is said that the Government itself is awaiting answer. What is the progress?

DR. RAJA RAMANNA: The present situation is, we are awaiting answers. There have, of course, been media reports of various types. But we cannot depend on them. We are waiting for an official answer.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I would like to put this second supplementary. It came in newspapers recently that the construction of a similar submarine in the Mazagon Dockyard has been delayed considerably. I would like to know whether it is because of this problem with the HDW. Or what are the other reasons why the progress of the construction of the submarine based on this design has been delayed in the Mazagon Dockyard?

DR. RAJA RAMANNA: There have been some delays. But they have nothing to do with this particular aspect of the case. The delay in the Mazagon Dockyard can be attributed to several internal problems.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, अगर मैंने ठीक सुना है, तो मंत्री महोदय ने कहा कि मीडिया की रिपोर्टस है और उन्होंने यह भी कहा है कि

मीडिया की रिपोर्ट्स पर रिलाई नहीं कर सकते । जो डिप्लोमेटिक चैनल्स से 1985 से लेकर आज 1990 हो गया, इतनी देर तक बैठे रहने का क्या कारण है ?

क्या उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स या उनकी ओर जो रिपोर्ट्स है, वह यह कनफर्म करती है कि एच.डी.डब्ल्यू. ने कान्ट्रेक्ट को ब्रीच किया है और अगर ब्रीच किया है, तो क्या एच.डी. डब्ल्यू. को ब्लैक लिस्ट करने के लिये सरकार विचार करेगी ?

DR. RAJA RAMANNA: Sir, as soon as the Government got to know that such transactions have taken place, I think we have taken immediate action to find out the truth. These things happened many years ago and could have been found out by the Government at that time. But they have not done it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is more than five yeas. I can understand that the previous Government did not do it. But what is the reason why this new Government has not taken it up immediately?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He has given a certificate to the previous Government. He said the Government promptly acted on it. (*Interruptions*).

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, on 29th March, 1990, 'Stern', a very respected magazine, gave this article with the heading 'U-Boat Affairs—Lies, Bribes and Betrayal' by Hubert Seipel which referred to confidential letters dated 28th October 1983, written by Ernst Pieper, addressed to Dr. Gernard Stoltenberg, the then Federal Minister for Finance, enclosing a note on the South African project, code-named 'IK-97'. This note, dated 6th October 1983 *inter alia* stated as follows:

"A. Customer wants to buy one set of production documents relating to the submarines which are being built in HDW for India as per IKL drawing.

B. The data are to go over the border as micro firms in diplomatic bags are to be collected."

The leading national newspaper published and it was picked up by others. Immediately the matter was reviewed and a note *verable* was presented by the Ministry of External Affairs to the Ambassador of FRG in New Delhi on 13-4-1990 seeking assistance and cooperation of the Government of FRG in the matter and requesting them to allow permission to the Public Prosecuter-in-Chief to investigate thoroughly into the matter and allow the investigation to reach their conclusive end without hindrance so that the truth behind the continuing allegations would be brought to light. So the Government immediately acted.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, if they are found guilty, will they be blacklisted?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, we will follow the rules and the law of the land.

MR. CHAIRMAN: Shri Dipen Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, from the reply given by the hon. Minister of State for Defence and also by the Prime Minister it is known that as soon as the present Government had come to know of the existence of this agreement, they had initiated certain action. But it appears that the agreement was signed on 29th April, 1985. Will the Minister kindly tell us whether the previous Government or for that matter, the Government which was existing at that time, had known the existence of this agreement and if so, what steps that Government had initiated? ... (*Interruptions*) ...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He can give first-hand information. He was a Minister in that Government.

DR. RAJA RAMANNA. It is quite clear that no action was taken in the earlier part of these negotiations. It is only when the press reported, as was read out by the Prime Minister, immediate action was taken within a few days to find out what the truth is and it looks as though the FRG is taking its time because obviously there must be some reasons, but we do not have the full and correct information, recorded information from the FRG. So we have to wait for sometime.

MR. CHAIRMAN: Shri M. C. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Chairman, Sir, this is quite shocking, though not unexpected, particularly because of our leading stand on the economic sanctions against South Africa. Now I know that these diplomatic moves are on, *note verbale* and all that, but consistent with the stand of the present Government, not to await the full inquiry but even pending inquiry, does the Government propose taking any action against FRG in this matter?

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I do not know what the hon. Member means by "taking action".

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: By temporarily blacklisting.

DR. RAJA RAMANNA: I do not believe that you can temporarily blacklist anyone without any information.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: You have not done it... (*Interruptions*)...

DR. RAJA RAMMANA: It is not just possible to temporarily blacklist anyone without information. That is not done.

MR. CHAIRMAN: Shri Yashwant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, obviously the matter that we are discussing is of very great national importance became it is a question of defence secret being leaked out to a country with which we have decided not to have any relationship. We seem to be dependent today too much not only on media report but on what the FRG Government does. What I would like to know specifically from the honourable Minister is whether he is aware that there is a proposal in the Bundestag, that is, the German Parliament, for inquiring into this matter and there are certain statements made by responsible Members of the German Parliament asserting that these secrets or these drawings and designs have been passed on to the South African Government. And, in the light of that, will the Government of India continue to depend on the sweet will of the German Government alone to find out the truth or will it activate its own agencies—we have Embassy in Bonn and we have other agencies at our command—to get at the truth without any loss of time?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, we are alert. But, to get information regarding a company there, a public sector company, wherein the Federal and the State Governments have shares. I mean, the States there, we will have to have the help of the Government there and we have to make that request. But, certainly, other agencies are alert and as and when any clues come, we will think of taking action on this and on the other matter also and our agencies are alert.

MR. CHAIRMAN: Next Question No. 187.